RPF SI & CONSTABLE 2024

रेल रक्षक बैच

ECONOMICS

औद्योगिक और विदेशी नीति



LIVE STREAMING 19-06-2024 11AM

⊙ औद्योगिक नीति (Industrial-policy) →

- देश में औद्योगिक क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार द्वारा इस नीति को बनाया जाता है।
- उत्पादन उद्योगों में किया जाता है।

- नीतियां → (1) प्रथम औद्योगिक नीति →
  - घोषणा → 6 अप्रैल 1948
  - श्यामाप्रसाद मुखर्जी द्वारा ✓
  - इसमें मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को अपनाया ✓
  - स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति ✓

मिश्रित (सरकार + निजी क्षेत्र)

(2) दूसरी औद्योगिक नीति (Second-Industrial-policy) →

- 30 अप्रेल 1956
- दूसरी पंचवर्षीय योजना ✓
- उद्योगो का विभाजन - ③
  - (1) प्रथम श्रेणी के उद्योग → 17
  - (2) द्वितीय श्रेणी के उद्योग → 13
  - (3) तीसरी श्रेणी के उद्योग → शेष उद्योग ✓

तीसरी औद्योगिक नीति → 23 दिसम्बर 1977

Third-Industrial-policy (जार्ज फर्नांडिस)

- रोजगार ↑

नई आर्थिक नीति → 24 जुलाई 1991

3 आयाम → LPG

- उदारीकरण (Liberalization).
- निजीकरण (Privatization)
- वैश्वीकरण (Globalisation).

क्षेत्र

- विदेश नीति (foreign-policy).
- विदेशी विनिमय नीति (foreign-exchange-policy) (FEP).
- व्यापार नीति (Trade & commerce-policy).
- औद्योगिक नीति, 1991.

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU)
Public-sector-unit

सरकारी उद्यम / कंपनी को PSU कहा जाता है।

विभाजन (3)
- महारत्न
- नवरत्न
- मिनीरत्न
  - प्रथम श्रेणी
  - द्वितीय श्रेणी

⊙ विदेशी व्यापार
(Foreign-Trade)

एक देश का अन्य देशों के साथ, आयात और निर्यात, विदेशी व्यापार कहलाता है।

यह व्यवस्था, खुली अर्थ-व्यवस्था (open-economy) में पाई जाती है।

कारण → FDI को आकर्षित करना ✓
(Foreign-Direct-Investment)
(प्रत्यक्ष विदेशी निवेश)

- विदेशी व्यक्ति द्वारा पूंजी और तकनीक का घरेलू सीमा में अंतप्रवाह ✓

- फायदा → रोजगार ↑
  - उत्पादन ↑
  - बेरोजगारी ↓

विदेशी व्यापार को बढ़ाने के प्रयास ✓

- सरल और आसान नीतियों को लाना ✓
- SEZ (special-economic-zone).
  विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना ✓
  - 5 वर्षों तक Tax मे राहत ✓
- FTA (free-Trade-Agreement) को बढ़ावा देना ✓
  (स्वतंत्र व्यापार नीति).

⊙ NOIDA
New-Okhla-Industrial
Development-Authority.